डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अप्रैल, 2023, डिस्पेच दिनांक 1 अप्रैल, 2023

| वर्ष 66 | अंक 21 | भोपाल | 1 अप्रैल, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का उद्घाटन किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अंतर्गत दो दिवसीय वैश्विक मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (आईवाईएम)-2023 पर एक डाक टिकट और मुद्रा सिक्के का अनावरण किया। इसके साथ ही श्री मोदी ने वैश्विक मिलेटस (श्री अन्न) सम्मलेन के शुभारम्भ अवसर पर भारतीय कदन्न अनुसन्धान संसथान का श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में लोकार्पण किया।

इस दौरान उन्होंने कहा, "ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत की प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है और आज मुझे गर्व है कि भारत 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' का नेतृत्व कर रहा हैं।"

पीएम मोदी ने आगे श्री अन्न योजना की तारीफ की और प्राकृतिक व श्री अन्न की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। आगे श्री मोदी ने कहा कि श्री अन्न कैमिकल मुक्त खेती

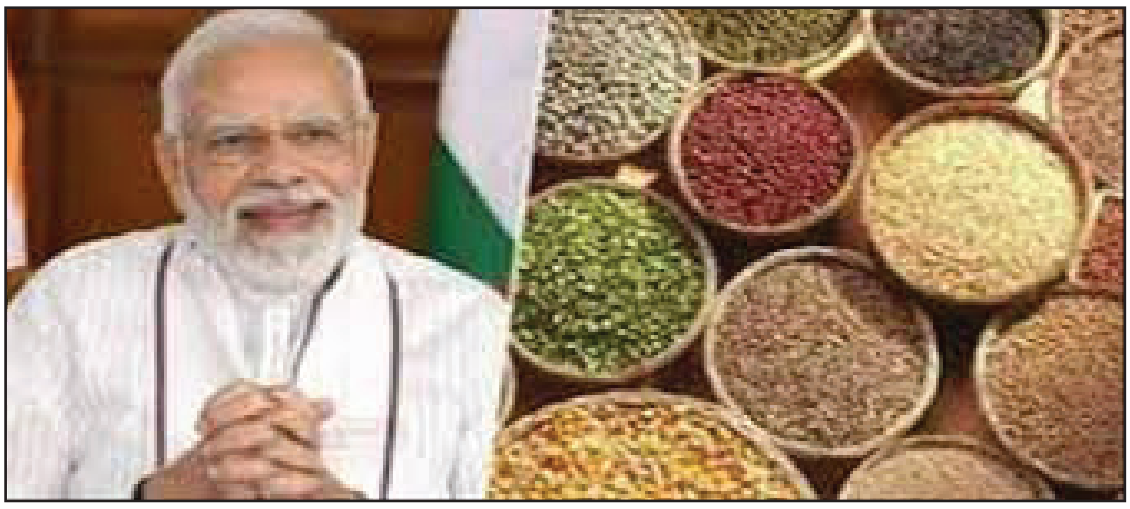

का बड़ा आधार हैं और यह प्राकृतिक क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में भी मददगार साबित होते हैं। साथ ही श्री अन्न द्वारा देश के आदिवासी समाज का भी सत्कार होगा। श्री मोदी ने मिलेट का भढ़ाना देने के लिए कहा," मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग और कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स को श्री अन्न के रूप में पहचान दी गई है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि और समग्रता भी होती है।"

श्री अन्न सम्मेलन का उद्देश्य बताते हुए हैं मोदी जी ने कहा, "भारत सरकार का लक्ष्य हैं कि, इस वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन से किसानों, उपभोक्ताओं के सम्रग लाभ और जलवायु के लिए एक जन आंदोलन बनाना हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं आईवीएमएम-2023 के लक्ष्यों को हासिल करने और भारत को 'मोटे अनाजों के वैश्विक केंद्र' के रूप में स्थापित करने के लिए बहु-हितधारक सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना है। मोटे अनाज को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए सरकार श्री अन्न वर्ष 2023 में विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाये जा रहे हैं, ताकि श्री अन्न फिर से हमारे भोजन का हिस्सा बन सकें।"

श्री अन्न की खेती कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। यह छोटे किसानों की समृध्दि का द्वार हैं साथ ही श्री अन्न करोड़ो लोगों के पोषण का कर्णधार हैं। कंगनी श्री अन्न प्रोटीन, फाइबर और विटामिन व पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से कंगनी को सकारात्मक अनाज का नाम देते हुए 'सुपरफूड' की श्रेणी में रखा गया है।

पीएम मोदी ने किया हमारा मार्गदर्शन- कृषि मंत्री

किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्री अन्न सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "यह मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष के शुभारंभ का उत्सव है। मिलेट्स के विषय को लेकर जब भी कोई सवाल आया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्साह से हम सबका मार्गदर्शन किया और उसी के परिणामस्वरूप यह कार्यकम उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जितना भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी तरह से विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, दुनिया के सामने विद्यमान चुनौतियों का समाधान हो सके, इसके लिए भी उनका प्रयास रहता है।"

श्री अन्न गलोबल मीटिंग में 75 लाख से अधिक किसान हुए शामिल

नई दिल्ली में चल रहे सम्मेलन में भारत के 75 लाख से अधिक किसान आज वर्चुअली प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आज ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) कॉन्फ्रेंस में मिलेट्स की खेती, संबंधित अर्थव्यवस्था व किसानों की आय समेत अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग ने विचार-विमर्श किया।

इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग द्वारा किसानों को खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज (श्री अन्न) के बारे में जागरुकता बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास और विस्तार में निवेश बढ़ाना व श्री अन्न की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना है।

इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह मिलेट्स कॉफ्रेंस 19 मार्च 2023 को खत्म होगी।

मध्यप्रदेश को सिंचाई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी बधाई

भोपाल : केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो ने प्रदेश को सिंचाई क्षेत्र में हुए कार्यों के लिए उत्कृष्ट राज्य चुना है। ब्यूरो "सीबीआईपी अवार्ड" के लिये मध्यप्रदेश की मोहनपुरा एवं कुण्डालिया परियोजना के सफल क्रियान्वयन के आधार पर नामांकन दाखिल किया गया था। मध्य प्रदेश ने जल संसाधन के दक्षतम उपयोग में प्रथम स्थान अर्जित किया है।

मध्यप्रदेश को यह अवार्ड 3 मार्च को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह ने प्रदान किया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज विधानसभा समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक शुरू होने के पहले जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और विभागीय अमले को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के लिए निरंतर निर्णय लिए और प्रदेश की अनेक सिंचाई योजनाएँ मंजूर कर उन्हें क्रियान्वित भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के विजन एवं विशेष प्रयासों से गत 15 वर्ष से राज्य के सिंचित क्षेत्र को 8 लाख हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की दृढ़-इच्छा शक्ति से पिछले 3 साल में मध्यप्रदेश में नवीन तकनीक का प्रयोग कर प्रेशर पाईप प्रणाली से पानी खेतों तक पहुँचाया गया है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 21.03.2023

क्रमांक File No: 1/1/3/0001/2022-Sec-2-15(COP) : : राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 8 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2022 के अंतर्गत दिनांक 22.2.2023 को विभागीय चयन समिति की आयोजित बैठक में निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले सहायक आयुक्त सहकारिता संवर्ग के निम्न अधिकारियों जिनको प्रथम समयमान वेतनमान (उप आयुक्त सहकारिता पद का वेतनमान) का लाभ प्राप्त हो रहा है, को प्रशासनिक सुविधा एवं कार्य संचालन की दृष्टि से उच्च पद उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं का पदनाम दिया जाकर आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम क्र. 4 में दर्शाई गई पदस्थापना अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री अखिलेश चौहान	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल
2	कुमारी वर्षा श्रीवास	सहायक आयुक्त सहकारिता जिला झाबुआ	उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धार
3	श्रीमती आरती पटेल	सहायक आयुक्त सहकारिता जिला उमरिया	उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल
4	डॉ. छविकांत वाघमारे	सहायक आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल	उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रायसेन
5	सुश्री दीप्ति वनवासी	सहायक आयुक्त सहकारिता जिला सीधी	उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला सीधी
6	सुश्री श्वेता रावत	मुख्यालय	उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल

2/ उपरोक्त अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं पद का दिये जा रहे पदनाम निम्न शर्तों के अधीन रहेगा :-

1. यह व्यवस्था मात्र प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य संचालन की दृष्टि से किये जाने के कारण यह आदेश विभागीय भर्ती नियम, 2022 के नियम 15 (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) के अध्यधीन रहेगा।
2. विभागीय भर्ती नियम, 2022 के नियम 14 के अंतर्गत उल्लेखित नीति अनुसार पदनाम का यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
3. अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं पद का पदनाम प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के अंतर्गत अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने पर किया जावेगा।
4. इस आदेश के आधार पर उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा वर्तमान में प्राप्त कर रहे लाभों के अतिरिक्त अन्य कोई दावा नही किया जावेगा और न ही अधिकारी द्वारा इस आदेश के आधार पर उच्च पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वत्वों की मांग कर सकेगा।
5. यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सहकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2022 तथा राज्य शासन के अन्य नियमों के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक लागू रहेगा, जो किसी भी समय शासन द्वारा निरस्ती योग्य होगा तथा यह आदेश किसी भी सक्षम न्यांयालय में चुनौती योग्य नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
21/3/2023
(गायत्री पाराशर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

क्रमांक File No: 1/1/3/0001/2022-Sec-2-15(COP) भोपाल दिनांक 21 मार्च, 2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
3. विशेष सहायक मा. मंत्री जी सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन विभाग म.प्र. भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
5. कलेक्टर जिला धार/सिंगरौली/सीधी/रायसेन/झाबुआ/उमरिया।
6. संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर/शहडोल/भोपाल/रीवा।
7. उपायुक्त सहकारिता/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला धार/सिंगरौली/सीधी/ रायसेन/ झाबुआ/ उमरिया/भोपाल ।
8. संबंधित अधिकारी।
9. उप संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।
10. आदेश फोल्डर।

21/3/2023
अवर सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 21.03.2023

क्रमांक File No: 1/1/3/0001/2022-Sec-2-15(COP) :: राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 8 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2022 के अंतर्गत दिनांक 22.2.2023 को विभागीय चयन समिति की आयोजित बैठक में निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले संयुक्त आयुक्त सहकारिता संवर्ग के निम्न अधिकारियों जिनको तृतीय समयमान वेतनमान (अपर आयुक्त सहकारिता पद का वेतनमान) का लाभ प्राप्त हो रहा है, को प्रशासनिक सुविधा एवं कार्य संचालन की दृष्टि से उच्च पद अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं का पदनाम दिया जाकर आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम क्र. 4 में दर्शाई गई पदस्थापना अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री ब्रजेश शरण शुक्ल,	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मुख्यालय, भोपाल	अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुख्यालय भोपाल
2.	डा. अनिल कुमार	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं शहडोल संभाग	अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुख्यालय भोपाल
3.	श्री पी.एस. तिवारी	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं प्रभारी प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं प्रभारी प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (समकक्ष पद - अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं)

2/ उपरोक्त अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं पद का दिये जा रहे पदनाम निम्न शर्तों के अधीन रहेगा :-

1. यह व्यवस्था मात्र प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य संचालन की दृष्टि से किये जाने के कारण यह आदेश विभागीय भर्ती नियम, 2022 के नियम 15 (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) के अध्यधीन रहेगा।
2. विभागीय भर्ती नियम, 2022 के नियम 14 के अंतर्गत उल्लेखित नीति अनुसार पदनाम का यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
3. अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं पद का पदनाम प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के अंतर्गत अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने पर किया जावेगा।
4. इस आदेश के आधार पर उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा वर्तमान में प्राप्त कर रहे लाभों के अतिरिक्त अन्य कोई दावा नही किया जावेगा और न ही अधिकारी द्वारा इस आदेश के आधार पर उच्च पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वत्वों की मांग कर सकेगा।
5. यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सहकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2022 तथा राज्य शासन के अन्य नियमों के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक लागू रहेगा, जो किसी भी समय शासन द्वारा निरस्ती योग्य होगा तथा यह आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
21/3/2023
(गायत्री पाराशर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

क्रमांक File No: 1/1/3/0001/2022-Sec-2-15(COP) भोपाल दिनांक 21 मार्च, 2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
3. विशेष सहायक मा. मंत्री जी सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन विभाग म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर जिला शहडोल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल।
6. संयुक्त आयुक्त सहकारिता/ उपायुक्त सहकारिता शहडोल।
7. संबंधित अधिकारी।
8. उप संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।
9. आदेश फोल्डर।

21/3/2023
अवर सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

वन नेशन-वन राशन योजना का लाभ सभी को मिलना सुनिश्चित करें : गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश 2023 और अमृत काल 2047 सुशासन से संबंधित मंत्री समूह की बैठक

भोपाल : गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने वन नेशन-वन राशन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। मंत्री डॉ. मिश्रा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश 2023 और अमृत काल 2047 सुशासन से संबंधित मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 7 विभागों के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा की गई। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, पशुपालन मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राशन मिलने में होने वाली गड़बड़ी से संबंधित दोषियों का चिन्हांकित कर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। हितग्राहियों को राशन लेते ही उनके मोबाइल पर हिन्दी में एसएमएस भेजने के पुख्ता प्रबंध करें।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने योजनाओं से अधिकतम पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में पेक्स सोसायटी के डिजिटाइजेशन का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही इस लक्ष्य को पूर्ण भी किया जायेगा। पेक्स के बेहतर संचालन के लिये आवश्यक प्रबंध भी किये जा रहे हैं। आगामी एक साल में 10 हजार पंचायतों में पेक्स सोसायटी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का समय पर लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की सार्थकता तभी है, जब तत्परता से जनता लाभान्वित हो।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि योजनाओं का लाभ मैदानी स्तर पर ग्रामीणों को उपलब्ध हो। उन्होंने सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के निर्देश दिये।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, जनजातीय कार्य, लोक सेवा प्रबंधन, पशुपालन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, राजस्व तथा परिवहन विभाग की समीक्षा की गई।

प्रदेश को कृषि में अव्वल बनाना हमारा लक्ष्य : कृषि मंत्री श्री पटेल

विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश को कृषि के हर क्षेत्र में अव्व्ल बनाने के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में सभी आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल विधानसभा के बैठक कक्ष में कृषि विभाग की परामर्शदात्री समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री श्री पटेल ने विभाग की प्रमुख गतिविधियों, प्रदेश की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों एवं कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य किये जाने संबंधी विषयों पर आवश्यक निर्देश दिये। विधायक सर्वश्री देवीलाल धाकड़, राजेंद्र पांडेय और प्रद्युमन सिंह लोधी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अशोक वर्णवाल, संचालक कृषि एम. सेल्वेंद्रम, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड श्रीमती जी.वी. रश्मि और जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अपर मुख्य सचिव कृषि श्री वर्णवाल ने जानकारी दी कि प्रदेश दलहन फसलों में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में देश के कुल दलहन उत्पादन का 21 प्रतिशत, खाद्यान्न में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 10 प्रतिशत, कुल राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन का 19 प्रतिशत उत्पादन होता है। प्रदेश गेहूँ उपार्जन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 तक लगातार विभिन्न श्रेणी में कृषि कर्मण पुरूस्कार प्राप्त करता रहा है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में गुड-गवर्नेंस इण्डेक्स में राज्य का पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ग्रीष्मकालीन मूंग से कृषकों को रु. 80 हज़ार से 1 लाख 20 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त आय हुई है।

कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों में प्रदेश, देश का इकलौता राज्य है, जिसने एम.पी. फार्म गेट मोबाइल एप द्वारा कृषकों को कहीं से भी अपनी कृषि उपज बेचने का विकल्प दिया है। एप पर अब तक कुल 91 लाख मीट्रिक टन उपजों के सौदे संपादित हुए हैं। कृषि संबंधित विभिन्न जानकारी एवं सेवा- जैसे मण्डी भाव, योजनाओं की जानकारी, मौसम आधारित कृषि सलाह इत्यादि समन्वित मोबाइल एप पर कृषकों हेतु उपलब्ध है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश द्वारा ई-उपार्जन पंजीकरण से लेकर किसान के खाते में राशि का पारदर्शी हस्तांतरण का कार्य किया जा रहा है।

फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किसान आगे आएं

भोपाल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना के तहत किसान फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे आएं। जिससे आमदनी बढ़ सके एवं आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण से प्रदेश में प्रसंस्करण की काफी संभावनाएं हैं। प्रत्येक जिले में एक विशेष उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन एवं प्रदर्शन भी किया गया है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री जे. एन. कंसोटिया ने भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण एक्सपो 2023 में दी।

एक्सपो में श्री कंसोटिया ने कहा कि प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की दिशा में प्रयास करना होंगे, उन्होंने कहा कि बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है अब आंवले का जीआई टैग होने की संभावना है। इसके पूर्व कार्यक्रम के प्रारंभ में संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण सुश्री निधि निवेदिता ने योजनाओं एवं कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मंबई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एम.व्ही. मुरलीकृष्णा, जीआई एक्सपर्ट एवं ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी, इंटरनेशनल डेलीगेट्स जापान के श्री कोयची फुकावा भी उपस्थित थे। एक्सपो में उन्नत कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई।

गेहूँ उपार्जन हेतु स्लॉट बुक एक अप्रैल से

सागर :जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार सागर जिले में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य 2125 रू. प्रति क्विटल की दर से गेहूँ उपार्जन का कार्य दिनांक 1 अप्रैल 15 मई तक किया जाएगा। गेहूँ उपार्जन हेतु जिले में 114 उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। जिसमें 72 गोदाम स्तरीय 31 समिति स्तरीय एवं 11 मंडी परिसर में केन्द्र स्थापित किये गये है। किसान बंधुओं से गेहूँ विक्रय करने हेतु निकटवर्ती उपार्जन केन्द्र पर अपना स्लॉट बुक करने का अनुरोध किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 21.03.2023

क्रमांक **File No:** 1/1/3/0001/2022-Sec-2-15(COP) : : राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 8 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2022 के अंतर्गत दिनांक 22.2.2023 को विभागीय चयन समिति की आयोजित बैठक में निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले उप आयुक्त सहकारिता संवर्ग के निम्न अधिकारियों जिनको द्वितीय समयमान वेतनमान (संयुक्त आयुक्त सहकारिता पद का वेतनमान) का लाभ प्राप्त हो रहा है, को प्रशासनिक सुविधा एवं कार्य संचालन की दृष्टि से उच्च पद संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं का पदनाम दिया जाकर आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम क्र. 4 में दर्शाई गई पदस्थापना अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्रीमती सुरभि वार्ष्णेय	प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित भोपाल	प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित भोपाल
2	श्री ऋतुराज रंजन	प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल	प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल
3	श्री अमरेश कुमार सिंह	प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित भोपाल	प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित भोपाल
4	श्री एम. के. गुप्ता	उपायुक्त सहकारिता जिला उज्जैन	संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) सहकारी संस्थाएं इंदौर संभाग इंदौर
5	श्रीमती अरूणा दुबे	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल	सचिव म.प्र. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ भोपाल
6	श्री विमल कुमार श्रीवास्तव	रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल	सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल
7	श्री अरूण कुमार मिश्रा	मुख्यालय	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
8	श्रीमती कीर्ति सक्सेना	मुख्यालय	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल
9	श्री यतीश त्रिपाठी	सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल	सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल
10	श्री महेन्द्र दीक्षित	उपायुक्त सहकारिता जिला धार	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं उज्जैन
11	श्री राकेश कुमार पाण्डेय	मुख्यालय	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं नर्मदापुरम
12	श्री कांति कुमार द्विवेदी	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल	सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल
13	श्रीमती सुरेखा अहिरवार	उपायुक्त सहकारिता जिला विदिशा	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी शहडोल
14	डा. शिवेन्द्र देव पाण्डेय	मुख्यालय	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी सागर
15	सुश्री अनीता उइके	मुख्यालय	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी चम्बल संभाग मुरैना
16	श्री विनोद कुमार सिंह	उप पंजीयक (न्यायिक) सहकारी संस्थाएं भोपाल	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी भोपाल
17	श्री मनोज कुमार सिन्हा	मुख्यालय	पदेन उप सचिव, सहकारिता (मुख्यालय)
18	श्री संजय मोहन भटनागर	सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल
19	श्री हितेन्द्र सिंह वाघेला	मुख्यालय	मुख्यालय
20	श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह	उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी ग्वालियर
21	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल	प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल
22	श्री संजय मौर्य	प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल	प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल

2/ उपरोक्त अधिकारियों को प्रवर श्रेणी संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं पद का दिये जा रहे पदनाम निम्न शर्तों के अधीन रहेगा :-

1. यह व्यवस्था मात्र प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य संचालन की दृष्टि से किये जाने के कारण यह आदेश विभागीय भर्ती नियम, 2022 के नियम 15 (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) के अध्यधीन रहेगा।
2. विभागीय भर्ती नियम, 2022 के नियम 14 के अंतर्गत उल्लेखित नीति अनुसार पदनाम का यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
3. अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं पद का पदनाम प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के अंतर्गत अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने पर किया जावेगा।
4. इस आदेश के आधार पर उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा वर्तमान में प्राप्त कर रहे लाभों के अतिरिक्त अन्य कोई दावा नही किया जावेगा और न ही अधिकारी द्वारा इस आदेश के आधार पर उच्च पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वत्वों की मांग कर सकेगा।
5. यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सहकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2022 तथा राज्य शासन के अन्य नियमों के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक लागू रहेगा, जो किसी भी समय शासन द्वारा निरस्ती योग्य होगा तथा यह आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
21/3/2023
(गायत्री पाराशर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

क्रमांक **File No:** 1/1/3/0001/2022-Sec-2-15(COP) भोपाल दिनांक 21 मार्च, 2023

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
3. विशेष सहायक मा. मंत्री जी सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन विभाग म.प्र. भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल।
6. कलेक्टर जिला धार/उज्जैन/भोपाल/विदिशा/सीहोर।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल।
8. संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर/भोपाल/उज्जैन।
9. उपायुक्त सहकारिता जिला धार/उज्जैन/भोपाल/विदिशा/सीहोर।
10. संबंधित अधिकारी।
11. उप संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।
12. आदेश फोल्डर।

21/3/2023
अवर सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

(पृष्ठ 1 का शेष)

मध्यप्रदेश को सिंचाई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए...

पाईप प्रणाली से सिंचाई कर नहर प्रणाली की तुलना में समान जल में दोगुने से भी अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने वाले पहले राज्य के रूप में मध्यप्रदेश की पहचान बनी है।

केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो ने प्रदेश को सिंचाई क्षेत्र में हुए कार्यों के लिए उत्कृष्ट राज्य चुना है। ब्यूरो "सीबीआईपी अवार्ड" के लिये मध्यप्रदेश की मोहनपुरा एवं कुण्डालिया परियोजना के सफल क्रियान्वयन के आधार पर नामांकन दाखिल किया गया था। मध्य प्रदेश ने जल संसाधन के दक्षतम उपयोग में प्रथम स्थान अर्जित किया है।

मध्यप्रदेश को यह अवार्ड 3 मार्च को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह ने प्रदान किया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज विधानसभा समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक शुरू होने के पहले जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और विभागीय अमले को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के लिए निरंतर निर्णय लिए और प्रदेश की अनेक सिंचाई योजनाएँ मंजूर कर उन्हें क्रियान्वित भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के विजन एवं विशेष प्रयासों से गत 15 वर्ष से राज्य के सिंचित क्षेत्र को 8 लाख हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की दृढ़-इच्छा शक्ति से पिछले 3 साल में मध्यप्रदेश में नवीन तकनीक का प्रयोग कर प्रेशर पाईप प्रणाली से पानी खेतों तक पहुँचाया गया है। पाईप प्रणाली से सिंचाई कर नहर प्रणाली की तुलना में समान जल में दोगुने से भी अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने वाले पहले राज्य के रूप में मध्यप्रदेश की पहचान बनी है।

भविष्य की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पौध आधारित खेती महत्वपूर्ण विकल्प – श्री तोमर

नई दिल्ली: भविष्य में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत विकल्प में पौध आधारित आहार पर विचार विमर्श करने के लिए गत दिनों प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित आहार प्रदर्शनी के दौरान पौध आधारित युग के उषाकाल विषय पर प्लांट बेस्ड फ़ूड इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (पीबीएफआईए) द्वारा आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौध आधारित कहदी वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही रोज़गार के अवसर सृजित करने और कृषि क्षेत्र को भी बल देने वाला है। जो चुनौतियाँ कृषि के सामने आ रही है , उनके मद्देनज़र पौध आधारित आहार वैकल्पिक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने वाले विकल्पों को अगर हम अभी से तैयार कर लेंगे तो आने वाले समय में संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों में खाद्य सुरक्षा भी इन्हीं में से एक है। जब देश की आज़ादी के100 वर्ष पूरे होंगे तब तक आबादी भी बढ़ जाएगी। आधुनिक और विकसित भारत के लिए अधोसंरचना विकास , नई रेल लाइनें ,नेशनल हाइवे जैसे कार्यों के लिए खेती का रकबा कम होने की सम्भावना को भी देखना होगा। 2047 तक भारत को विकसित महान राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार तेज़ी से राज्य सरकारों के साथ मिलकर जुटी हुई है।वर्ष 2050 तक कितने खाद्यान्न की आवश्यकता हमें होगी। दुनिया की अपेक्षा हमसे कितनी बढ़ेगी इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। इस दिशा में केंद्र सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समग्र और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी का हमेशा आग्रह रहा है कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आना चाहिए। इससे नई पीढ़ी कृषि की ओर आकर्षित होगी। किसान खेती का आधार है। यह बात समझनी होगी। किसानों को फायदा और प्रतिष्ठा देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए , ताकि वह खेती में रुके। देश का पेट भर सके और दुनिया की अपेक्षा को भी पूरा कर सके। सरकार इस दिशा में सतत प्रयास कर रही है।

श्री तोमर ने कहा खाद्य सुरक्षा के साथ ही पोषक दृष्टि से भी विकल्प तैयार करना समय की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। श्री अन्न का उत्पादन -उत्पादकता , प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और निर्यात बढ़े , इससे बने पदार्थों को भोजन की थाली में पुनः प्रतिष्ठापूर्ण स्थान मिले इसलिए यह वर्ष मनाया जा रहा है। इससे पोषक तत्वों का आहार बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम में पीबीएफआईए के पदाधिकारी श्री संजय सेठी , एपीडा के सचिव डॉ सुधांशु और आईटीपीओ के श्री रजत अग्रवाल भी मौजूद थे।

उपार्जन कार्य की जरूरी तैयारियाँ पूरी करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में रबी उपार्जन कार्य के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य के लिए की गई तैयारियों संबंधी बैठक में यह निर्देश दिए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन के लिये करीब 15 लाख किसान पंजीयन करवा चुके हैं। गत वर्ष हुए पंजीयन की तुलना में तीन चौथाई पंजीयन हो चुके हैं। लगभग 20 लाख पंजीयन होने की संभावना है। अनाज के भण्डारण एवं परिवहन के लिए आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं।

प्रदेश में 25 मार्च से गेहूँ उपार्जन शुरू होगा। संभागवार तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में 25 मार्च से उपार्जन प्रारंभ होगा। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चम्बल संभाग में एक अप्रैल से उपार्जन कार्य प्रारंभ होगा। प्रदेश में 4 हजार 223 उपार्जन केंद्र कार्य करेंगे। बारदाना व्यवस्था में करीब 3 लाख गठान की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार प्रबंध हो चुका है। वर्तमान में उपलब्ध बारदानों से लगभग 70 लाख मीट्रिक टन उपार्जन संभव है। भण्डारण के लिए भारतीय खाद्य निगम, अधिग्रहित गोदाम, ओपन केप, सायलो बैग सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय एजेंसियों के गोदाम उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रमुख निर्देश

- भण्डारण क्षमता अच्छी रखें।
- उपार्जन केंद्र पर्याप्त हों।
- बारदाने की कहीं भी कमी न हो।
- किसान को समय पर राशि का भुगतान हो।
- आवश्यक परिवहन व्यवस्था हो।
- उपार्जन से जुड़े कार्यों में तकनीक का उपयोग हो।
- किसान को उपार्जन के लिए खुद केंद्र के चयन की सुविधा दी जाए।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को समय पर राशि का भुगतान किया जाए।

डिण्डौरी में तैयार हो रहे है कोदो-कुटकी के उत्पाद और रेसिपी

प्रधानमंत्री ने की थी प्रंशसा

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स (मोटा अनाज) वर्ष घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। मिलेट्स की पौष्टिक तत्व और बेहतर गुणवत्ता होने से विदेशों में अधिक माँग है। मध्यप्रदेश में अलग-अलग इलाकों में विभिन्न प्रकार के मिलेट्स का उत्पादन और उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के डिण्डो री जिले की श्रीमती लहरी बाई की "मन की बात" में प्रशंसा भी की।

महिला एवं वित्त निगम की सहायता से डिण्डौरी में कोदो-कुटकी के विभिन्न उत्पाद और व्यंजन रेसिपियाँ तैयार की गई हैं। कोदो-कुटकी बर्फी, कुकीज, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन और खिचड़ी इत्यादि तैयार किये जा रहे हैं। इसके लिये विभिन्न ईकाइयाँ स्थापित की जाकर सफलता से संचालित की जा रही है।

मिलेट्स सभी तरह की स्थितियों के लिये अत्याधिक अनुकूल होते हैं। इन्हें पानी उर्वरक और कीटनाशकों की न्यूनतम आश्यकता होती है। अन्य अनाजों की तुलना में यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर माईक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल और बायोएक्टिव फ्लेवोनॉयड्स वाली पौष्टिक फसल है। प्रदेश का डिण्डोरी जिला मिलेट्स में कोदो-कुटकी के लिये विख्यात है। यह विलुप्त प्रजाति की लघु धान्य फसल है, जिसमें गेहूँ, चावल की अपेक्षा प्रोटीन, केल्शियम, आयरन, मेगनिशियम आदि सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत तादाद में उपलब्ध है। कोदो-कुटकी का ग्लासेमिक इन्डेक्स न्यून है। यह व्यक्ति को अधिक समय तक ऊर्जावान बनाये रखता है। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के आँगनवाड़ी केन्द्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। इससे पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में ओला-बारिश से नुकसान पर 32 हजार रु. प्रति हेक्टेयर की राहत

मुख्यमंत्री ने किया ओला-वृष्टि प्रभावित क्षेत्र का दौरा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओला-वृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32 हजार रूपए की राहत राशि दी जाएगी। साथ ही फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। उन्होंने उद्यानिकी फसलों को भी सर्वे में शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान चिंता न करें, परेशान न हों, सभी तरह के संकट से बाहर निकाल कर ले जाऊँगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के पटवारीखेड़ी, हथियाखेड़ा, घुरदा, मूडरागणेश और मढ़ीचौबीसा गाँव में ओला-वृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को ढाँढस बंधाया।

श्री चौहान ने किसानों से कहा कि एक हेक्टेयर फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 32 हजार, गाय-भैंस हानि पर साढ़े 37 हजार, भेड़-बकरी पर 4 हजार बछिया पर 2 हजार और मुर्गा-मुर्गी की हानि पर 100 रूपए प्रत्येक के मान से राहत राशि दी जाएगी। मकानों को हुई क्षति पर भी सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली की तारीख तो बढ़ाई ही जायेगी साथ ही ब्याज भी सरकार ही भरेगी और अगली फसल के लिए भी जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिलाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के लिए तारीख भी बढ़ाई जाएगी।

33758 हेक्टेयर की फसल प्रभावित

प्रारंभिक सूचना के मुताबिक प्रभावित जिलों की 51 तहसीलों के 520 ग्रामों में 38 हजार 900 कृषकों की 33 हजार 758 हेक्टेयर फसल प्रभावित होने की प्रारंभिक सूचना है।

इन जिलों में बदला मौसम

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, विदिशा, रायसेन, झाबुआ, मंदसौर, रतलाम, नीमच, बैतूल, राजगढ़, सागर, सतना, छतरपुर, दमोह, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सीहोर, बालाघाट, बुरहानपुर, भिंड, शिवपुरी, खंडवा, हरदा, मुरैना, धार, डिंडोरी, सिवनी, आगर, नरसिंहपुर, रीवा समेत कई जिलों में बारिश हुई।

जैविक खेती अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं किसान- स्वास्थ्य मंत्री

रायसेन :स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नकतरा में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी का कन्यापूजन और दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान खुशहाल हों, सम्पन्न हों, समृद्ध हों, उनकी आय बढ़े इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि किसानों को उन्नत और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रगतिशील किसानों के खेतों और कृषि विज्ञान केन्द्रों का भ्रमण कराकर, कृषि विज्ञान मेला, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से किसानों को खेती की उन्नत, नई तकनीकों की जानकारी देते हुए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान भाई जैविक खेती को अपनाएं, इसमें लागत कम होती है तथा मुनाफा अधिक होता है। उन्होंने बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल भी बनाया गया है, जिसमें जैविक खेती करने वाले किसान पंजीयन करा सकते हैं। सरकार द्वारा जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोटे

अनाज के उपयोग को दिया जा रहा है बढ़ावा कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशानुरूप मोटे अनाज (मिलेट) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें उन्नत बीज के साथ ही उन्नत कृषि तकनीकी संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नागरिकों को भी अपने आहार में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए जागरूक किया जाएगा। सरकार किसानों की आमदानी बढ़ाने और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। उन्नत खाद और बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगातार सिंचाई के रकबे में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उद्यानिकी, नगदी फसलों की खेती अपनाएं किसान भाई- जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए केन्द्र और प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों को परम्परागत खेती के अलावा उद्यानिकी, नगदी फसलों की खेती भी करनी चाहिए। जिले में टमाटर की बहुतायात में खेती की जाती है तथा जिले का टमाटर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी भेजा जा रहा है। जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा जिले की बासमती धान विदेशों में भी निर्यात की जा रही है। किसान भाई जैविक, प्राकृतिक खेती अपनाएं, उन्नत तकनीकों का उपयोग करें। इससे कम लागत में अधिक मुनाफा मिलेगा तथा किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे ने कहा कि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है तथा कृषि के क्षेत्र में नित नई उन्नति कर रहा है। चाहे गेहूँ हो, धान हो, मूंग हो, टमाटर हो या अन्य उद्यानिकी फसलें हों, उनकी उत्पादकता में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले से टमाटर का अनेक प्रदेशों में निर्यात किया जा रहा है। जिले में उत्पादित धान की भी अन्य प्रदेशों तथा विदेशों में काफी मांग है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस तरह के कृषि विज्ञान मेलों और प्रदर्शनी में अधिक से अधिक सहभागिता करनी चाहिए। इससे उन्हें खेती की उन्नत और नई तकनीकों की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रगतिशील किसानों से मिलकर उनसे सीखने का अवसर भी मिलता है। कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि शासन द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में भी लगभग 900 से अधिक किसानों द्वारा जैविक खेती के लिए पंजीयन कराया गया है, जिन्हें कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण तथा तकनीकी जानकारी के साथ ही सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि परम्परागत खेती के अलावा किसान कुछ रकबे में उद्यानिकी, औषधीय फसलों की खेती करें। इससे उन्हें कम लागत में अधिक मुनाफा मिलेगा। किसानों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि खेती में अधिक मात्रा में रसायनिक दवाओं, कीटनाशकों का उपयोग करने से स्वास्थ्य पर विपरीत असर तो पड़ता ही है। साथ ही मिट्टी की उर्वरकता शक्ति भी कम होती है। उन्होंने किसानों से कृषि फसल के अवशेषों, ठंठल, पराली नहीं जलाने की भी अपील करते हुए कहा कि इससे उर्वरक क्षमता कम होने के साथ ही कभी-कभी गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती है। जिनमें जान-माल की हानि हो जाती है। फसल अवशेषों को जैविक तरीके से खाद में परिवर्तित किया जा सकता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2661 उद्यानिकी किसानों को नई तकनीक से अवगत कराया

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक

भोपाल :प्रदेश के उद्यानिकी कृषकों को खेती की नई तकनीक और उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने जिले, प्रदेश और प्रदेश के बाहर भ्रमण करा कर प्रशिक्षित किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 2661 किसान को प्रशिक्षण दिया गया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। विधायक सर्वश्री मनोज चावला, सुभाष रामचरित, गोपाल सिंह चौहान, अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया उपस्थित थे।

संचालक उद्यानिकी सुश्री निधि निवेदिता ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फल पौध-रोपण योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 247 हेक्टेयर में पौध-रोपण के लिये किसानों को 3 करोड़ 84 लाख 31 हजार रूपये का अनुदान दिया गया है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में 28 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के उत्पादन के लिये कृषकों को अनुदान दिया गया है। व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना में 10 हजार 677 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिये किसानों को सहायता दी गई है। उद्यानिकी खाद्य प्र-संस्करण योजना में एक करोड़ 88 लाख 23 हजार रूपये का अनुदान दिया गया है।

बताया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 4 हजार 240 कृषक को लाभान्वित किया गया है। युवाओं को माली प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5 प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौ-शालाओं को उद्यानिकी रोपणियों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना में 10 संभाग मुख्यालयों के जिलों की उद्यानिकी रोपणियों के साथ 10 गौ-शालाओं को जोड़ा गया है। रोपणी उन्नयन योजना में प्रदेश की 14 रोपणियों के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। प्याज भंडार गृह, राइपनिंग चेम्बर, कोल्ड-रूम, पैक हाउस, प्लास्टिक लाइनिंग ऑफ फार्म पोण्ड, उच्च तकनीक से पान की खेती, संरक्षित खेती, फल क्षेत्र विस्तार, संकर सब्जी और पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना, जैविक खेती, चैनलिंक फेंसिंग और एमआईडीएच की प्रगति की जानकारी दी गई। एमडी एमपी एग्रो श्री संजय गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जबलपुर में पशुपालन के उन्नत तरीके विषय पर प्रशिक्षण सम्पन्न

जबलपुर: अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत पशुपालन के उन्नत तरीके विषय पर गत दिनों तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन डॉ. जे.एस.मिश्र, निदेशक, खरपतवार अनुसंधान निदेषालय, जबलपुर के मुख्य अतिथ्य में आयोजित किया गया। इस आयोजन में अनुसूचित जाति के किसानों सहित 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डॉ.जे.एस.मिश्र ने उद्घाटन समारोह में बताया कि कृषि एवं पशुपालन आपस में जुड़े हुए है। पशुपालन के उन्नत तरीके अपनाकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं । किसानों की आय दुगुनी करने में उन्नत तरीके से पशुपालन भी सहायक सिद्ध हो सक इस अवसर पर डॉ. पी.के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक ने किसानों से आह्वान किया कि उन्नत नस्लें अपनाकर एवं वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन कर इसे भी लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. योगिता घरडे वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी (अनु.जा.उप.यो.) ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य से अवगत कराते हुए किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित किया। अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के किसानों को पशुपालन से संबंधित उपकरणों का वितरण भी किया गया। इस आयोजन में श्री घनश्याम विश्वकर्मा का विशेष सहयोग रहा।

रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को मिला जीआई टेग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी बधाई

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर्ष का विषय है कि प्रदेश के रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टेग मिलने से वैश्विक पहचान मिली है। इस गौरवपूर्ण सम्मान के लिए रीवा और मुरैना के भाई-बहनों एवं सभी प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल का आभार माना है।

मत्स्य सहकारी समितियो का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

उज्जैन। नागदा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में मत्स्य सहकारी संस्थाओं का तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम 16 मार्च से 18 मार्च 2023 तक चम्बयल सागर कालोनी नागदा में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नपा नागदा अध्यक्ष प्रतिनिधि व सांसद प्रतिनिधि ओ.पी. गेहलोत एवं नपा उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम में मत्स्य क्षेत्र में सहकारिता का महत्व, रिकार्ड संधारण, व्यवसाय विकास सहकारी प्रबंध मत्स्य बीज आहार रोग लक्षण उपचार, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के मुख्य प्रावधान, संचालक मंडल की भूमिका, अधिकार कर्तव्यर, आमसभा, शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षार्थियों को व्यवसायिक अध्ययन भ्रमण हेतु पाडल्या तालाब में मत्स्य आखेट रख रखाव और क्रय विक्रय से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। मत्स्य समितियों के सभी प्रतिभागियों से परिचर्चा कर अतिथियों द्वारा समस्याओं का समाधान किया गया। श्री नवीन बाथरी, मत्स्य निरीक्षक, श्री शांतिलाल चौहान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, श्री धमेन्द्र गुप्ता, प्राचार्य, शेष शायी महाविधालय नागदा तथा दिलीप मरमट, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम में सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग समिति का सहयोग सराहनीय रहा । कार्यक्रम के अन्त में सभी का आभार सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के प्राचार्य दिलीप मरमट द्वारा किया गया।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देशभर में सहकारिता पर हो रहा शानदार कार्य : गणेश जोशी

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित मध्य क्षेत्र के राज्यों के लिए सहकारी विकास पर सम्मेलन में किया प्रतिभाग

कृषि के क्षेत्र में विपणन के लिए सहकारी समितियों का अहम योगदान : गणेश जोशी

मसूरी। उत्तराखण्ड प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 24.03.2023 मसूरी में एक निजी होटल में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित मध्य क्षेत्र के राज्यों के लिए सहकारी विकास पर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सम्मलेन में उत्तराखण्ड सहित मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ मणिपुर सहित विभिन्न राज्यों के अधिकारीगण एवं प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विपणन के लिए सहकारी समितियों का अहम योगदान है। मंत्री ने कहा आज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की लाखों बहने लाभ ले रही है। देश में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की बजाय सहकारिता क्षेत्र सर्वोपरि हैं। क्योंकि शायद ही कोई ऐसा सामाजिक क्षेत्र होगा, जहां सहकारिताएँ कार्यरत नहीं हैं। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ देश की राष्ट्रीय राज्य और बहु–राज्यीय सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान में 85 लाख से अधिक सहकारी समितियां जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहकारी संघ का हिस्सा हैं जो देश भर के तीस करोड से अधिक आबादी के जीवन को स्पर्श करती हैं। मंत्री जोशी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) देश में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्षस्थ संगठन हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ देश में सहकारिता आंदोलन के शीर्षस्थ संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों हेतु शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि सहकारिता से जुडे सदस्यों और कार्मिको हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सकें।

उन्होंने कहा स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए एनसीयूआई द्वारा हॉट और इनक्युबेशन केंद्र की भी स्थापना की गई हैं। प्रदेश में ग्राम्य विकास के अधीन भी हमने इसी तर्ज पर रूरल इनक्युबेशन (आरबीआई) की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाये हैं। मंत्री जोशी ने कहा केन्द्र में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश भर में सहकारिता पर बहुत शानदार कार्य हो रहा है।

मंत्री जोशी ने कहा कि सहकारिता ही एक ऐसा मॉडल है जिसमें धन की शक्ति बुद्धि की शक्ति और श्रम की शक्ति एक निश्चित उद्देश्य को लेकर एक दिशा में कार्य करती है और प्राप्त लाभांश को बराबर–बराबर बाटती हैं। इसी क्रम में सहकारी समितियों से संबंधित महत्वूपर्ण नीतिगत मुद्दों पर राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर भी सम्मेलन सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित किए जा रहें हैं।

मंत्री ने कहा इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य जोनल क्षेत्रों के राज्यों हेतु जोनल सम्मेलन का आयोजन मसूरी, उत्तराखण्ड में किया जा रहा हैं जिसमें सभी हितधारकों से विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा और नीतिगत मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने कहा निश्चित ही इस सम्मलेन के माध्यम से जो मंथन निकलकर आएगा वह प्रदेश के सशक्त उत्तराखण्ड के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ दिलीप संधणी, डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव, डॉ. सुनील कुमार सिंह, के. शिवदासन नामर, बिजेन्द्र सिंह, बी.एल. मीणा, आदित्य चौहान, डॉ. सुधीर महाजन, रेशम फेडरेशन, अध्यक्ष अजीत चौधरी, मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, मोहन पेटवाल, कुशाल राणा, सहित गई लोग उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के गोदाम प्रभारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण

भोपाल। श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के जिलो में कार्यरत गोदाम प्रभारियों हेतु "(एम.आई.एस.) आई. एफ.एस.एस. पोर्टल पर उर्वरक एवं भण्डारण व्यवसाय का संचालन" विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 17 मार्च 2023 को रखा गया था। प्रशिक्षण में विषय की सारगर्भिता को दृष्टिगत रखते हुए अतिथि वक्ताओं के द्वारा (एम.आई.एस.) आई.एफ.एस. एस. पोर्टल के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के श्रीमति मंदिरा लोधी, डी.जी.एम.आई. टी., श्री नितेन्द्र सिंह, मैंनेजर आई. टी, श्री सौरभ गुप्ता, प्रोग्रामर, श्री शैलेन्द्र सिंह, साफ्टवेयर कन्सलटेन्ट, श्री उमेश बोन्डे, प्रोग्रामर आदि ने पोर्टल से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के जिलो में कार्यरत गोदाम प्रभारियों को श्री यतीश त्रिपाठी सचिव, एवं म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ तथा श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक, श्री धनराज सैंदाणे लिपिक, श्री विक्रम मजुमदार, लिपिक, श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव, प्रशिक्षक श्री राहुल नगरिया भृत्य एवं कार्यालय के अन्य सदस्यों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्रीमति मीनाक्षी बान एवं सहयोगी श्री विनोद कुशवाह द्वारा किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।